भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2720

11 अगस्त, 2021 को उत्तर के लिए

इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण

2720. डा. सी. एम. रमेश:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में विभिन्न इस्पात संयंत्रों के कार्य निष्पादन को बेहतर करने के लिए संयंत्रों के आधुनिकीकरण का विचार रखती है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितने इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण किया गया है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिए कोई निधि आवंटित की गई है और यदि हां, तो आधुनिकीकरण पर कितनी धनराशि खर्च की गई है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री (श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह)

(क) और (ख): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और मंत्रालय की भूमिका एक सुविधाप्रदाता की है। इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण का निर्णय अलग-अलग कंपनियों द्वारा तकनीकी-वाणिज्यिक सोच-विचारों के आधार पर लिए जाते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र की दो इस्पात कंपनियाँ अर्थात् स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) ने पिछले दशक के दौरान अपने इस्पात संयंत्रों का उत्तरोत्तर आधुनिकीकरण किया है। इनमें सेल के भिलाई (छत्तीसगढ़), बोकारो (झारखंड), राउरकेला (ओडिशा), दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल), बर्नपुर (पश्चिम बंगाल) स्थित और आरआईएनएल के विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश) स्थित इस्पात संयंत्र शामिल हैं।

(ग): भारत सरकार ने इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए कोई निधि आवंटित नहीं की है। इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण को संबंधित इस्पात क्षेत्र की कंपनियों द्वारा उनके अपने आंतरिक संसाधनों/उधार से वित्तपोषित किया जाता है।

****